P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-2* May (Part-1)- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में गरीबी की समस्या एवं समाधान का एक अध्ययन

टी.आर. रात्रे
सहायक प्राध्यपक
अर्थशास्त्र विभाग,
गुरु घासी दास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर, छत्तासगढ़, भारत

नमिता शर्मा
सहायक प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग,
गुरु घासी दास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर, छत्तासगढ़, भारत

सारांश

यह एक सामाजिक क्रिया में है जिसमें समाज का एक बड़ा भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता। जब समाज का एक बड़ा अंग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है और केवल निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है।

भारत एक विकासशील एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है यहां की कुल आबादी जनगणना 2011 के अनुसार 121.07 करोड़ है, जिसमें 36.30 करोड़ जनसंख्या निर्धन है। गरीबी एक सामाजिक अभिशाप है, भारत की जनसंख्या में जनसंख्या का एक बड़ा भाग लगभग 29.5% गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे है। जिसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। इनके पास, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, कपड़े, रोजगार का अभाव है और यह जनसंख्या निम्न जीवन स्तर पर जीने को मजबूर है। भारत में स्वतत्रंता के पश्चात् सरकार में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके राज्य एवं स्थानीय सरकारों को वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों का आबंटन किये है, ग्रामीण एवं शहरी रोजगार कार्यक्रम भी चलाये जा रहे है। परिणाम स्वरूप गरीबी अनुपात प्रतिशत में कमी आयी है। किन्तु निर्धनों की संख्या अभी भी उच्च स्तर पर बना हुआ है जो कि भारतीय समाज एवं देश के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

मुख्य शब्द : भारत में निर्धनता अनुपात, समस्या एवं सुझाव।

प्रस्तावना

भारत देश को प्राचीन समय में ''सोने का चिड़िया'' कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत का विदेश व्यापार मजबूत रहा था। किन्तु भारत में बढ़ती आबादी, अग्रेजी शासन की शोषणवादी नीतियों तथा देश में अस्थिर राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण होने के कारण तथा देश में संसाधनों की कुशलतम आबंटन निर्धन वर्गो में नहीं होने तथा धन एवं आय की असमानता होने के कारण भारत में गरीबी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अभी भी सर्व व्याप्त है।

भारत में कुल 29 राज्य है जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर, अरूणांचल प्रदेश जहां 35% से अधिक गरीबी है। यह जनसंख्या निम्न वर्ग में से है। भारत में 1973–74 में गरीबों का अनुपात 54.9% था जो कि जनगणना 2011 के अनुसार 29.9% कुछ कमी आयी है। भारत में बहुत से अर्थशास्त्रियों एवं संस्थाओं ने गरीबी के निर्धारण के लिए अपने–अपने प्रमाप बनाये है। 1979–80 के पश्चात् छठवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास प्रारंभ हुआ तब से आज तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार कार्यक्रम चलाये जा रहे है। किन्तु यह निर्धनों की संख्या के अनुपात में बहुत कम है। भारत में सभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे बड़े देश के कुल जनसंख्या से अधिक जनसंख्या भारत में गरीबी रेखा के नीचे है जो कि भारत जैसे विकासशील देश के सामने, इसे निपटने के लिए विशेष चुनौती है।

तालिका क्रमांक 01
भारत में निर्धनता अनुपात (वर्ष 2011–12)

क्रमांक	समूह	निर्धनता अनुपात (प्रतिशत में)			निर्धनों की संख्या (मिलियन)		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1.	रंगराजन समूह	30.9	26.4	29.5	260.5	102.5	363.0
2.	तेन्दुलकर समूह	25.7	13.7	21.9	216.7	53.1	269.8

स्रोत :– योजना आयोग, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका 01 में स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 में रंगराजन समूह ने गरीबी अनुपात 29.5% एवं निर्धनों की संख्या 363.0 एवं तेन्दुलकर समूह ने 21.9% तथा 269.8 आंकलन किया है।

तालिका क्रमांक 02
अखिल भारतीय निर्धनता रेखा

विशेषज्ञ समूह	वर्ष	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय(रू.)		प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय		निर्धनता रेखा (औसत मासिक उपभोग व्यय 5 व्यक्तियों के परिवार हेतु	
		ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण	नगरीय
रंगराजन समिति	2011–12	32.4	46.9	972	1407	4760	7035
तेल्दुलकर समिति	2011–12	27.2	33.3	816	1000	4080	5000

स्रोत :– योजना आयोग, भारत सरकार।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 02 से स्पष्ट है कि अलग–अलग विशेषज्ञ समूह ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय एवं प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय का आंकलन किया है। रंगराजन समूह ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 32.4 एवं 46.9 रूपये तथा तेन्दुलकर समिति में क्रमशः 27.2 एवं 33.3 रूपये आंकलन किया है। अखिल भारतीय निर्धनता रेखा 5 व्यक्तियों के परिवार के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए रंगराजन समिति में 4760 एवं 7035 तथा तेन्दुलकर समिति ने 4080 तथा 5000 रूपये है।

तालिका क्रमांक 03
रंजराजन विशेषज्ञ समूह द्वारा विकसित निर्धनता मापन विधि के आधार पर राज्यवार निर्धनता अनुपता तथा निर्धनों की संख्या

क्र.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	निर्धनता अनुपात (प्रतिशत)	निर्धनों की संख्या (लाख)
1.	आन्ध्रप्रदेश	13.7	117.3
2.	अरूणाचंल प्रदेश	37.4	5.3
3.	टसम	40.9	129.5
4.	बिहार	41.3	438.1
5.	छत्तीसगढ़	47.9	124.8
6.	दिल्ली	15.6	26.7
7.	गोवा	6.3	0.9
8.	गुजरात	27.4	168.8
9.	हरियाणा	12.5	32.4
10.	हिमांचल प्रदेश	10.9	7.5
11.	जम्मू कश्मीर	15.1	19.3
12.	झारखण्ड	42.4	142.5
13.	कर्नाटक	21.9	135.7
14.	केरल	11.3	38.3
15.	मध्यप्रदेश	44.3	327.8
16.	महाराष्ट्र	20.0	228.3
17.	मणिपुर	46.7	12.9
18.	मेघालय	24.4	7.4
19.	मिजोरम	27.4	3.1
20.	नागालैण्ड	14.0	2.8
21.	उड़ीसा	45.9	195.0
22.	पंजाब	11.3	31.6
23.	राजस्थान	21.7	151.5
24.	सिक्किम	17.8	1.1
25.	तमिलनायडू	22.4	163.9
26.	त्रिपुरा	24.9	9.3
27.	उत्तरप्रदेश	39.8	809.1
28.	उत्तराखण्ड	17.8	18.4
29.	पं. बंगाल	29.7	275.4
	अखिल भारत	29.5	3629.9

स्त्रोतः भारत सरकार, आर्थिक सर्वेक्षण, 2017–18

उपरोक्त तालिका क्रमांक 03 से स्पष्ट है कि भारत में सबसे अधिक गरीबी वाले राज्य क्रमशः उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, अरूणांचल प्रदेश, मणिपुर है जहां 35ः से ऊपर जनसंख्या निर्धन है तथा मध्यम श्रेणी वाले गरीबी राज्य, राजस्थान, गुजरात, पं. बंगाल, मिजोरम, मेघालय, कर्नाटक जहां 21% से अधिक जनसंख्या निर्धन है तथा सबसे कम गरीबी वाले राज्य गोवा 6.3% हिमाचल प्रदेश 10.9% केरल 11.3% पंजाब 11.3% है। भारत में औसत निर्धनता अनुपात 29.5% तथा निर्धनों की संख्या 36.30 करोड़ है जो कि बहुत अधिक है।

समस्यायें

भारत में जनसंख्या के एक बड़े भाग जिनके पास, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, कपड़े आदि की समस्या है। यह वर्ग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् है। भारत के कुल रोजगार में असंगठित क्षेत्र का योगदान 92.5% है जिनकी दैनिक मजदूरी दर 60 रू. से 160 रू. तक है जो कि प्रति व्यक्ति आय कम होने से बचत शून्य है तथा ये वर्ग साहूकार, महाजन, बैंको तथा अन्य वित्तीय संख्याओं में कर्ज में फंसे हुए है तथा बीमारी, कुपोषण, निम्न स्वास्थ्य से ग्रसित है। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर व मजदूरी दर कम है, कम आय होने के कारण ये वर्ग असहाय, दुर्बल एवं शोषित है। इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है।

सरकारी प्रयास

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (IRDP), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SRGY) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना (JAY), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्किम (MNREGA), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY), सन् 2022 तक सबके लिए

रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अन्त्योदय अन्न योजना आदि ग्रामीण एवं शहरी विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे है।

सुझाव

1. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात एवं निर्धनों की संख्या अधिक है, अतः ग्रामीण संसाधनों एवं कृषि पर आधारित विकास कार्यक्रमों पर सरकार को अधिक व्यय किया जाना चाहिए जिससे कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके।
2. ग्रामीण एवं शहरी दोनों में विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर अधिक बजट आबंटित किया जाना चाहिए जिससे कि ग्रामीण बच्चों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्तर बेहतर हो सके।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए MNREGA जैसे और बड़े विकास कार्यक्रम, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाया जाना चाहिए।
4. समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों तथा सामान्य जाति के कमजोर वर्गों के लिए विशेष विकास कार्यक्रम रियायतें, सहायता जैसे कार्यों के लिए केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों को समन्वय ढंग से कार्यप्रणाली विकसित किया जाना चाहिए।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में निर्धनों की संख्या अधिक है, इसका कारण यह है कि प्रति महिलाएं कुल प्रजनन दर 3 से 4 है। अतः परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करना चाहिए, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रित की जा सके।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में स्व–सहायता समूह, एन.जी.ओ. जैसे संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
7. वर्तमान में MNREGA की रोजगार दिवस 100 है इसे बढ़ाकर 150 दिवस किया जाना चाहिए तथा मजदूरी दर में 30% से अधिक वृद्धि किया जाना चाहिए जिससे कि उनकी आय एवं क्रय शक्ति में वृद्धि हो सके।
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गुणवत्ता, पारदर्शिता पूर्वक लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि निर्धन परिवारों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके।

निष्कर्ष

भारत में 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू की गई उस समय भारत में लगभग 56% गरीबी अनुपात रहा है। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की संयुक्त भागीदारी से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम चलाया गया, इससे रोजगार के अवसरों, आय, बचत, निवेश तथा अधोसंरचना के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, वर्ष 2011–12 में भारत में गरीबी अनुपात घटकर 29.9% रह गया किन्तु निर्धनों की संख्या में बेहताशा वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 36.30 करोड़ हो गया। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, बैंक, बाजार, सड़क, जलापूर्ति, विद्युत आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, मजदूरी दर निम्न है जिसके कारण उनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि समाज में निर्धनता एक सामाजिक अभिशाप है इसे दूर करना है तो न केवल सरकार बल्कि समाज के निजी क्षेत्रों, उद्योगपतियों, व्यवसायियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा बुद्धिजीवियों वर्गों को इनके हितों के लिए संयुक्त प्रयास किया जाना होगा, तभी समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान होगी, यदि समय पर समाधान नहीं किया गया तो आने वाले भविष्य में यह और अधिक गंभीर समस्या हो सकती है, जो कि सभ्य समाज के लिए कदापि उचित नहीं है।

References

Gaurav Dutt has poverty Declined since Economics Reforms ? Economic and political weekly Dec1999.

Govt. of India, planning commission report on 2011-2012.

Gaurav dutt and Ashwani Mahanjan "Indian Economy", p 361.

Report of the expert group to review the methodology for estimation of poverty planning commission Govt. of India, Nov 2009.

Govt. of India economics survey [2017-2018].

Dev, M. Mahendra and Ravi, C. proverty and inequality Economic and Political wickly Feb. 2007.